Office of the Principal, Govt. Mata Shabari Naveen Girls PG College, Bilaspur (C.G)
Near Patwari Prashikshan Kendra, Seepata Road Bilaspur (C.G) 495006
Contact No. 07752-240531, Mobile No. 8253021704
E-mail id : gmsngc1989@gmail.com www.gmsngcbsp.co.in
AISHE Code:- C-22358

Discipline and Anti Ragging Committee:- In order to ensure a ragging free and disciplined environment in the college campus, the college administration has formed a discipline and Anti Ragging committee. The members of the committee are:-

1.	Dr. Naaz Benjamin	-	Convenor
2.	Dr.Aarti Singh Thakur	-	Member
3.	Pro. Shobha Mahiswar	-	Member
4.	Dr.D.K.Shukla	-	Member
5.	Dr.R.K.Tiwari	-	Member
6.	Dr.Nishi Singh	-	Member
7.	Dr.Ishabel Lakra	-	Member
8.	Pro. Bela Mahant	-	Member
9.	Dr. Yatinandni Patel	-	Member

The discipline and Anti Ragging committee is sincerely committeeed to ensure a healthy academic environment for its students. The members of the committee keep a vigilant eye on the activities of the students to monitor that the norms and decorum of the college are maintained. The guidelines laid down by the Honorable Supreme court and UGC to fight menance of ragging in the education institution are displayed on the website. Anti ragging Posters are displayed and notice are continuously circulated in the classrooms and pasted at other sensitive spots in the college premises. At the time of induction programme of the students they are made aware of all the anti ragging policy of the college. C.C.TV camera have been installed in the Institution himself monitors the environment of the college.

(Dr. R. K. Verma)
Principal
Govt. Mata Shabari Naveen Girls PG College, Bilaspur(C.G.)

Following guidelines have been laid down by Hon'ble Supreme Court to fight menace of ragging in Educational Institutions.

1. The prospectus, the form for admission and/or any other literature issued to aspirants for admission must clearly mention that ragging is banned in the institution and any one indulging in ragging is likely to be punished appropriately.

2. If there be any legislation governing ragging or any, provisions in the Statute/Ordinances they should be brought to the notice of the students/patents seeking admissions.

3. Form for admission/enrolment shall have a printed undertaking to be filled up and signed by the candidate to the effect that he/she is aware of the institution's approach towards ragging and the punishments to which he or she shall be liable if found guilty of ragging. A similar undertaking shall be obtained from students already admitted and their parents.

4. A printed leaflet detailing when and to whom one has to turn for information, help and guidance for various purposes, keeping in view the needs of new entrants in the institution, alongwith the addressee and telephone numbers of such persons, should be given to freshers at the time of admissions so that the freshers need not look up to the seniors for help in such matters and feel indebted to or obliged by them.

5. The management, the principal, the teaching staff should interact with freshers and take them in confidence by apprising them of their rights as well as obligation to fight against ragging and generate confidence in their mind.

6. Institution to constitute a proctorial committee to keep a continuous watch and vigil over ragging and promptly deal with the incidents of ragging.

7. All vulnerable location shall be identified and specially watched.

8. Failure to prevent ragging shall be construed as an act of negligence on part of management, hostels wardens / superintendents.

9. The hostels/accommodations where freshers are accommodated shall be carefully guarded, and entry of seniors/outsiders to be regulated.

10. If individuals committing or abetting ragging are not identified collective punishment could be resorted to.

11. Migration certificate to contain entry indicating whether the student had participated in and in particular was punished for ragging.

12. Stoppage of financial assistance by UGC/funding agency to institutions falling to curb ragging.

13. Institution to face disaffiliation.

14. Institutions / Universities to hold activities where seniors and freshers can interact and develop friendly relationship.

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू नवीन अधिनियम्

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम, 2001

क्रमांक 27 सन् 2001*

[दिनांक 17 जनवरी, 2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 17 जनवरी, 2002 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उससे संबंधित मामलों और आनुषंगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ— (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम, 2001 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएँ— इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "रैगिंग" से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो, या किसी विधि पूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, या उसे क्षति पहुँचाना, या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना;

(ख) "शैक्षणिक संस्था" से अभिप्रेत है राज्य की कोई भी शासकीय अथवा अशासकीय शैक्षणिक संस्था।

3. रैगिंग का प्रतिषेध— किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

4. दण्ड— यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिये दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा या जुर्माने से जो 5 हजार रुपये से अधिक नहीं होगा या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

5. अपराध का संज्ञेय, अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होना— इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा।

* छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 17-1-2002 पृष्ठ 28-28 (1) पर प्रकाशित।

(123)

6. अपराधों का विचारण.— (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग के न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपराधों के अन्वेषण, जाँच तथा विचारण में अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) के उपबंध लागू होंगे।

7. छात्र के निष्कासन के लिये निर्योग्यता.— (1) इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा इसके छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा।

(2) किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र, जो धारा 4 के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा।

(3) ऐसे छात्र को जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया है, किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग,
मंत्रालय के पास, रायपुर

क्रमांक / .... / मा.अ.आ. / 2011 रायपुर, दिनांक

प्रति,

____

____

____

विषयः– रैगिंग रोकने के संबंध में।

–00–

राज्य की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक वर्ष 2011–12 प्रारम्भ हो रहा है, शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भिक दिनो में आयोग को विभिन्न माध्यमों से वरिष्ठ छात्रों के द्वारा कनिष्ठ छात्रों के प्रति अमानवीय व्यवहार "रैगिंग" के नाम से किये जाने की शिकायते प्राप्त होती रही है, जो मानव अधिकारों के उल्लंघन की श्रेणी में आते है। रैगिंग को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दण्डनीय अपराध बताकर रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम 2001 पारित किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी विश्व जागृति मिशन विरुद्ध केन्द्र शासन के प्रकरण में रैगिंग को रोके जाने हेतु दिशा निर्देश दिये गये है। उक्त दिशा निर्देशों का शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना एवं अध्ययनरत छात्र–छात्राओं से पालन करवाया जाना आवश्यक है।

रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम 2001 में रैगिंग को परिभाषित किया गया है, जिसमें किसी छात्र को मजाक पूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित हो या किसी विधि पूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना, या उसे क्षति पहुंचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी की दोष पूर्ण अवरोध, दोष पूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल का प्रयोग करना रैगिंग के अन्तर्गत आनेवाले कृत्य होगें।

रैगिंग एक गंभीर समस्या है इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है। रैगिंग के संबंध में शैक्षणिक संस्थाओं में "प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम" के अन्तर्गत दण्ड के प्रावधान है। शैक्षणिक संस्थाओं में छात्र–छात्राओं के बीच रैगिंग जैसे कार्यो को बढ़ावा न मिले एवं जूनियर छात्र छात्राओं में रैगिंग का भय व्याप्त न हो, इसके लिये शैक्षणिक संस्था में "रैगिंग रोकथाम समिति" का गठन किया जाये तथा रैगिंग के संबंध में यदि प्रकरण पाये जाते है तो त्वरित एवं कठोर कार्यवाही करते हुये आयोग को सूचित किया जावे।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विश्व जागृति मिशन विरूद्व केन्द्र शासन के प्रकरण में रैगिंग रोकने हेतु मागदर्शी दिशा निर्देशों की प्रति पालनार्थ संलग्न है। उक्त दिशा निर्देशों का पालन कर, पालन प्रतिवेदन से आयोग को अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(माननीय सदस्य/अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

विधि अधिकारी
छ.ग. राज्य मानव अधिकार आयोग,
रायपुर

(4)

DON'T RAG, JUST INTERACT

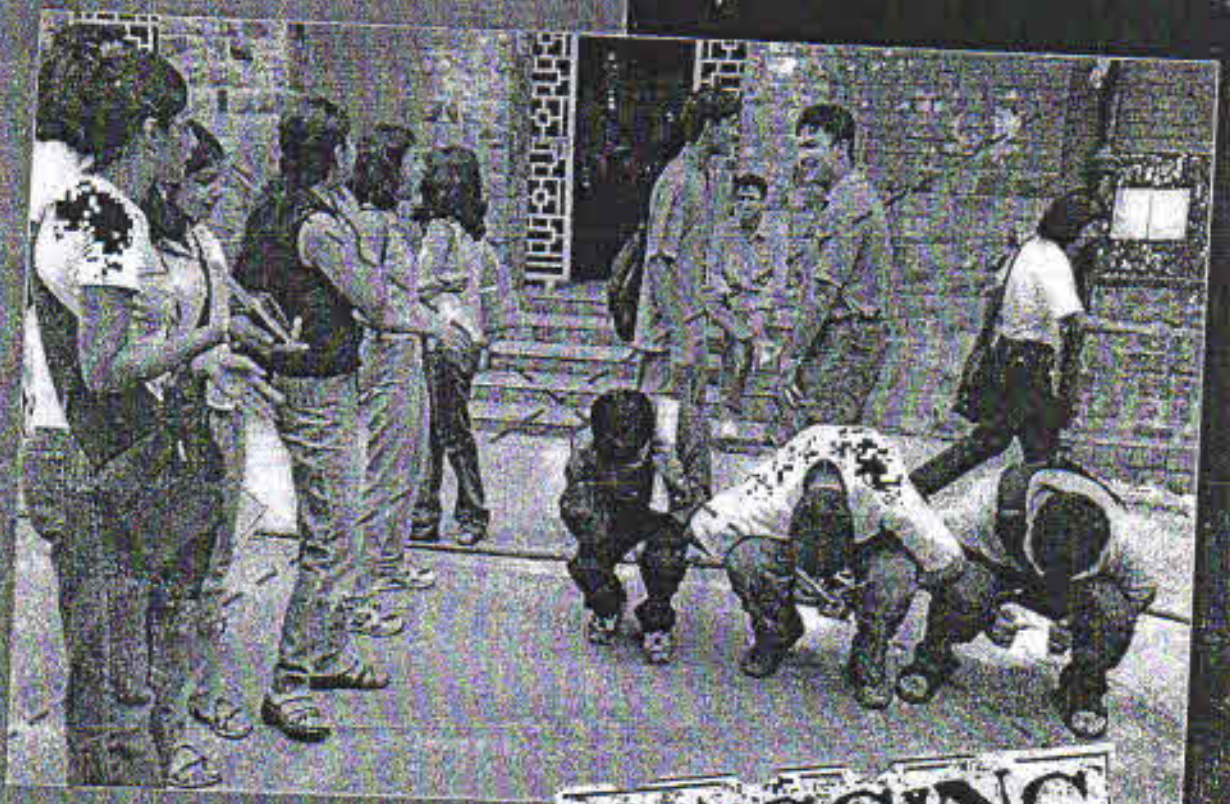

RAGGING IN ANY FORM IS PUNISHABLE

Visit UGC website i.e. www.ugc.ac.in & www.antiragging.in to see UGC Anti Ragging Regulations

Are you being ragged ?

Immediately call UGC Anti Ragging Helpline 1800-180-5522 (24X7 Toll Free) Or send an e-mail to helpline@antiragging.in

Download ANTI RAGGING App

Join hands to make your campus ragging free

MHRD | DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT GOVERNMENT OF INDIA

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग University Grants Commission

(5)

SAY NO TO RAGGING

BEFORE YOU EVEN THINK OF RAGGING

Download ANTI RAGGING App

THINK OF

- Humiliation
- Suspension
- Blacklisting
- Ruined Career
- Possible Prosecution
- Expulsion

Don't just stand and watch. Stop Ragging! Show Character

Remember RAGGING is for LOSERS

Visit UGC Website i.e. www.ugc.ac.in & www.antiragging.in to see UGC Anti Ragging regulations

Are You Being Ragged ?

Immediately call UGC Anti Ragging Helpline 1800-180-5522 (24x7 Toll Free)
Or Send an E-mail to helpline@antiragging.in

MHRD | DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(6)

Download
ANTI RAGGING
App

SAY NO TO RAGGING

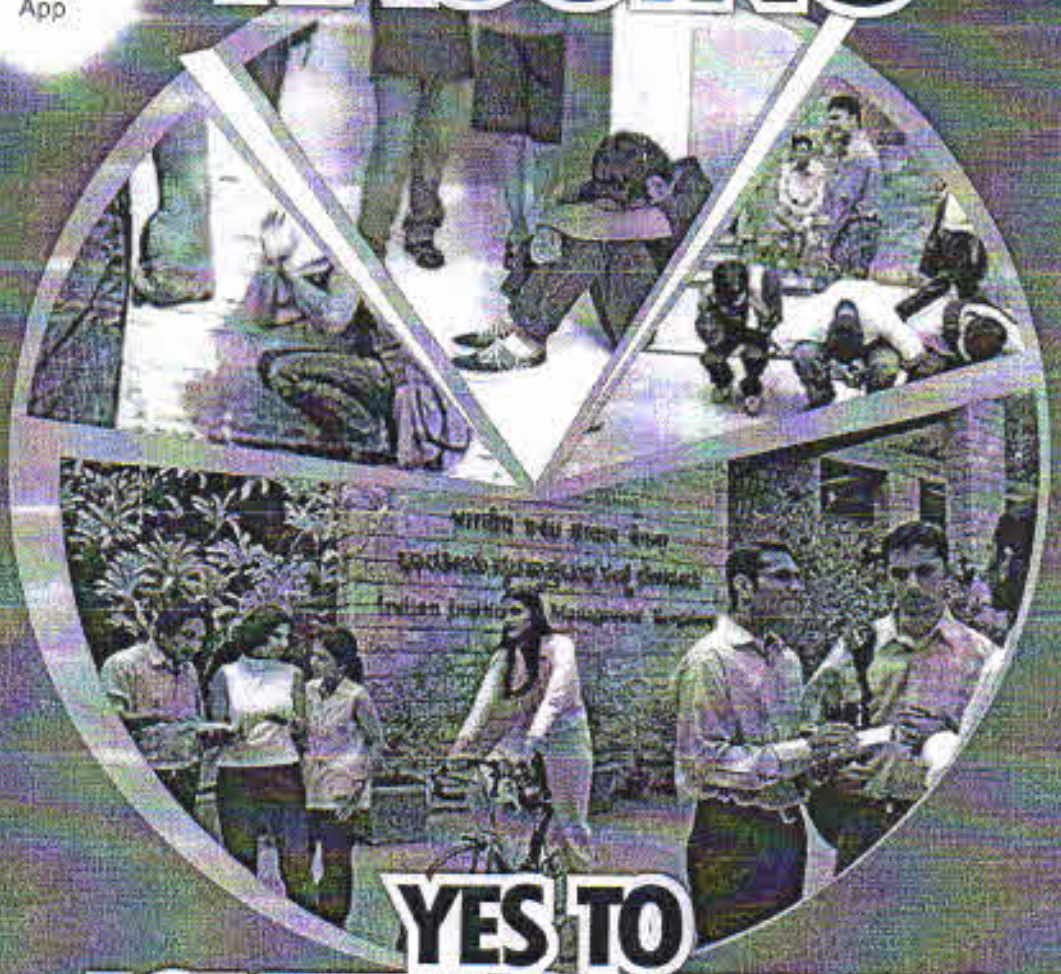

YES TO JOYFULCAMPUS

What is Ragging?

Any Act Resulting in:

- Mental/physical/sexual Abuse
- Verbal Abuse
- Indecent Behaviour
- Criminal Intimidation/wrongful Restraint
- Undermining Human Dignity
- Financial Exploitation/extortion
- Use Of Force

A STUDENT INDULGING IN RAGGING CAN BE:

- Cancellation of admission.
- Suspension from attending classes.
- Withholding/withdrawing Scholarship/Fellowship and other benefits.
- Debarring from appearing in any test/ examination or other evaluation process.
- Withholding results.
- Debarring from representing the institution in any regional, national or international meet, tournament or youth festival etc.
- Collective punishment : when the persons committing or abetting the crime of ragging are not identified the institution shall resort to collective punishment as a deterrent to ensure community pressure on potential ragger.

Immediately call
UGC Anti-Ragging Helpline
1800-180-5522 (24X7 toll free)
or send an e-mail to helpline@antiragging.in

MHRD | DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
quality higher education for all

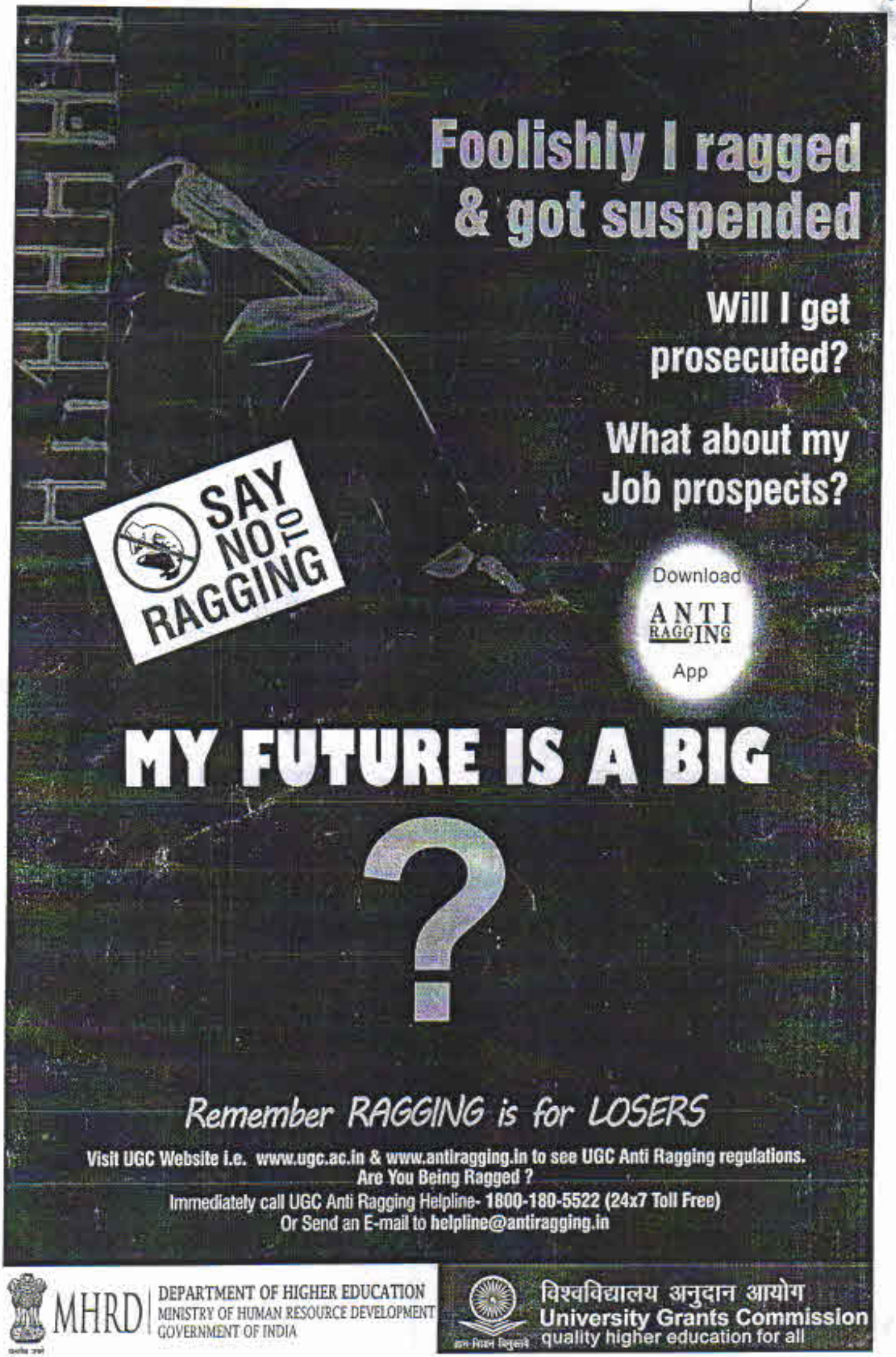

Foolishly I ragged
& got suspended
Will I get
prosecuted?
What about my
Job prospects?
SAY NO TO RAGGING
Download
ANTI RAGGING
App
MY FUTURE IS A BIG
?
Remember RAGGING is for LOSERS
Visit UGC Website i.e. www.ugc.ac.in & www.antiragging.in to see UGC Anti Ragging regulations.
Are You Being Ragged ?
Immediately call UGC Anti Ragging Helpline- 1800-180-5522 (24x7 Toll Free)
Or Send an E-mail to helpline@antiragging.in
MHRD
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
quality higher education for all